International Journal of Advance Research Publication and Reviews

Vol 02, Issue 08, pp 499-504, August 2025

छत्तीसगढ़ राज्य की आबकारी नीति एवं शराब उद्योग से राजस्व प्राप्ति का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Dr. Vijay Agrawal[1], Dr. Tapesh Chandra Gupta[2], Shweta Namdeo[3]

[1]Professor, J. Yoganandam Chhattisgarh Autonomous College Raipur Chhattisgarh, DrAkashNljn@gmail.com.
[2]Professor, J. Yoganandam Chhattisgarh Autonomous College Raipur Chhattisgarh. tapesh_48gupta@gmail.com
[3]Research Scholar, J. Yoganandam Chhattisgarh Autonomous College Raipur Chhattisgarh. Swetanamdeo85@gmail.com

सार–

छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं के लिए सभी प्रकार की शराब ६ बीयर की खुदरा बिक्री करता है। शराब, छत्तीसगढ़ में सबसे आम शराब उत्पाद है, जिस पर बड़े पैमाने पर कर नहीं लगता है और इसके उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए बहुत कम नियम हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ सरकार की स्वयं की कर प्राप्तियों का आकलन प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ में जिलों के पास कुछ निर्दिष्ट कर शक्तियां हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण हैं माल की बिक्री पर कराधान, मादक उत्पादों पर उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर और यात्री और माल कर, बिजली शुल्क, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क सहित परिवहन कर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2000 में एक अलग जिले के रूप में कर संग्रहण में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमने उद्योग के आर्थिक योगदान का अनुमान लगाने के लिए छत्तीसगढ़ में असंगठित शराब विनिर्माण फर्मों (एन = 241) के राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि सर्वेक्षण का उपयोग किया। छत्तीसगढ़ में शराब उद्योग के अपेक्षाकृत छोटे आर्थिक पदचिह्न को ध्यान में रखते हुए, शराब पर उच्च उत्पाद शुल्क और नियमों से समग्र स्तर पर आर्थिक विकास बाधित होने या छोटे शराब श्रमिकों के बीच बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाई पैदा होने की संभावना नहीं है।

कीवर्ड: अल्कोहल उत्पाद, छत्तीसगढ़ सरकार, शराब निर्माण, उत्पाद शुल्क, आर्थिक योगदान।

1. प्रस्तावना–

छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड संभालती है अतिरिक्त न्यूट्रल अल्कोहल, बीयर ६ वाइप से बना पीने योग्य शराब द्य पीने योग्य शराब एक उपभोज्य वस्तु है जिसमें अल्कोहल और अन्य रसायन शामिल हैं । किसी भी वस्तु की कोई भी उपलब्धता अगर नहीं है, तो संबंधित निर्माता का निर्णय है छत्तीसगढ़ में आइटम नहीं बेचने के लिए । जिस मूल्य पर वस्तु उपलब्ध है छत्तीसगढ़ में (किसी भी अन्य जगहों के मुकाबले) वस्तु का मूल्य अलग होने का कारण है निर्माता और राज्य द्वारा मूल्य निर्धारण शुल्क कानून के अनुसार ही होगा द्य सीएसएमसीएल शराब की खरीद करने और शराब की गुणवत्ता के मानकों को सुनिश्चित करने और उन्हें उपभोक्ताओं को जगह देने के लिए पर्याप्त कदम उठाती है। सीएसएमसीएल के माध्यम से लाई गई शराब बोतल के ढक्कन पर चिपकाए गए होलोग्राफिक स्टिकर को शामिल करता है। सीएसएमसीएल की गतिविधि सख्ती से छत्तीसगढ़ के उत्पाद शुल्क कानूनों और नियमों के अनुसार है। उपभोक्ता को पीने का निर्णय करते समय उसकी स्वास्थ्य स्थिति जानने की जरूरत है। शराब किसी भी अन्य उपभोज्य जैसा स्वतंत्र रूप से विपणन योग्य नहीं है लेकिन केवल लाइसेंस के माध्यम से बेचा जा सकता है द्य इस दृष्टि में, एक संदेश है कि उपभोक्ता को शराब लेने के दौरान अपने स्वास्थ्य की जांच करनी पड़ती है।

खुदरा अल्कोहल उत्पाद संयुक्त जिलों के कुछ सबसे अधिक विनियमित और कर वाले बाजारों में बेचे जाते हैं। उच्च करों या विनियमन को उचित ठहराने के लिए आम तौर पर दिया जाने वाला आर्थिक तर्क यह है कि शराब के सेवन से हिंसा और यातायात दुर्घटनाएँ जैसी बाहरी घटनाएँ होती हैं। हालाँकि, हालिया शोध बाहरीताओं को कम करने के लिए शराब कर नीति की प्रभावकारिता पर सवाल उठाता है, और संबंधित साहित्य थोक औरध्या खुदरा शराब बिक्री के नियामक विकल्पों में से सबसे नाटकीय जिला एकाधिकार के बारे में समान निष्कर्ष पर पहुंचता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार, जैसा कि सुझाव दिया गया है, जिला एकाधिकार का वास्तविक उद्देश्य जिला राजस्व में वृद्धि करना हो सकता है, एक तर्क जिसका विस्तार किया गया है और अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन किया गया है।

जिसके तहत प्रत्येक पांच वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाना निर्धारित किया गया है। वित्त आयोग एक सलाहकार निकाय है और केंद्र से जिलों को संसाधन के हस्तांतरण की सिफारिश करता है।

जिलों को विभाज्य पूल से कुछ धनराशि प्राप्त होती है और वे आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न कर लगाते हैं। चौदहवें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में जिलों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दी। राजस्व के अपने हिस्से में इस भारी गिरावट को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने पहले केंद्र द्वारा वित्त पोषित कई योजनाओं को बंद करके अनुदान सहायता को कम करने की रणनीति का सहारा लिया है।

आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और अन्य कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जिलों को कर योग्य और गैर–कर योग्य संसाधनों के माध्यम से अधिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। इस प्रकार, जिलों के राजस्व प्रयास उनके सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो बहुत महत्वपूर्ण जिले हैं और पूरे मध्य छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। आर्थिक और जनसांख्यिकीय आकार के मामले में बहुत भिन्न होने के बावजूद, इन जिलों के राजस्व प्रयासों का विश्लेषण और तुलना करना उचित है। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया।

शराब पीने पर अंकुश लगाने की सरकारी कार्रवाई के विरुद्ध, तर्क के दो घटक हैं। मांग पक्ष के परिप्रेक्ष्य का तर्क है कि शराब के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में पूरी जानकारी होने के बावजूद, धूम्रपान करने वालों को शराब पीने से उपयोगिता मिलती है। शराब को अक्सर गरीबों के लिए उपयोगिता के एक सस्ते स्रोत के रूप में देखा जाता है, भोग का एक रूप जो उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। हालांकि, जैसा कि अन्य शोधकर्ताओं का तर्क है, अपूर्ण जानकारी और स्वास्थ्य और वित्तीय बाहरीताओं सहित बाजार में काफी विफलताएं हैं। पीने से. हानिकारक प्रभावों के बावजूद, शराब पर कर बढ़ाने के खिलाफ प्रमुख तर्क यह धारणा है कि ऐसा कदम श्गरीब–विरोधीश होगा और श्शराब नियंत्रण के आर्थिक और सामाजिक परिणामोंष को नजरअंदाज कर देगा।

विशेष रूप से शराब उद्योग में नौकरी छूटने से लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए आजीविका का एकमात्र स्रोत खत्म हो सकता है। शराब उद्योग को अक्सर छोटे पैमाने के घरेलू स्तर के उद्योग के रूप में वर्णित किया जाता है, और यह दावा किया जाता है कि उपभोग कर, मांग को कम करके, शराब उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा और बदले में समग्र आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाएगा। हालाँकि, ये आपूर्ति पक्ष के तर्क वास्तविक साक्ष्य पर आधारित हैं।

शराब उद्योग में रोजगार, उत्पादन या मुआवजे जैसे आर्थिक मापदंडों पर सटीक अनुमानों की कमी संभावित शराब नियंत्रण कार्यों के परिणामों के बारे में अनिश्चितता में योगदान करती है। यह पेपर इस आपूर्ति पक्ष की बहस को खंडित करने के पहले प्रयासों में से एक है।

1.1 अध्ययन का उद्देश्य–

- मादक पेय पदार्थों की खपत के संबंध में उपभोक्ता व्यवहार और प्राथमिकताओं का अध्ययन करें।
- रोजगार सृजन, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान और शराब उद्योग से जुड़े अन्य आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण करें।

2. आंकडे एवं विधि–

हम छत्तीसगढ़ के एनएसएस 62वें दौर (2005–2006) से फर्म–स्तरीय डेटा का उपयोग करते हैं। इस सर्वेक्षण की एक विशेष प्रश्नावली में छत्तीसगढ़ के 4798 गांवों और 5125 शहरी ब्लॉकों में 8,897 असंगठित विनिर्माण उद्यमों पर डेटा एकत्र किया गया। डेटा में एक श्उद्यमश एक संगठनात्मक श्रेणी है – इनमें से लगभग 98ः उद्यम मालिकाना थे) जिसमें औसत कार्यबल का आकार केवल दो से अधिक श्रमिकों का होता है।

सर्वेक्षण में प्रत्येक फर्म की विभिन्न विशेषताओं, जैसे स्थान, स्वामित्व और संचालन की प्रकृति के साथ–साथ उत्पादन, बिक्री, व्यय, मूल्य वर्धित मूल्य, परिसंपत्ति होल्डिंग, रोजगार और श्रम आय सहित आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र की गई। सर्वेक्षण की गई फर्मों को छत्तीसगढ़ तालिका 1 के राष्ट्रीय उद्योग वर्गीकरण (एनआईसी 2004) कोड के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। हमारे विश्लेषण के लिए, हम केवल 2841 शराब निर्माण फर्मों (एनआईसी कोड 16002) के उप–नमूने पर विचार करते हैं। इससे हमारा अनुमान है कि 2005–2006 के दौरान छत्तीसगढ़ में 2.7 मिलियन से अधिक छोटे, असंगठित शराब उद्यम थे। हम इन फर्मों की निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियों का अनुमान प्रस्तुत करते हैं– बिक्री, सकल मूल्य वर्धित (जीवीए), रोजगार और मुआवजा।

तालिका 1 में छत्तीसगढ़ के शराब–विनिर्माण जिलों में शराब प्राप्तियों की हिस्सेदारी का अनुमान लगाया गया है।

जिला	कुल शराब प्राप्तियां	% असंगठित विनिर्माण उद्योग के रूप में शराब की बिक्री	समस्त विनिर्माण उद्योग में शराब की बिक्री % के रूप में
बिलासपुर	2,596	9.64	0.59
रायपुर	124	5.64	0.589

जिला	कुल शराब प्राप्तियां	% असंगठित विनिर्माण उद्योग के रूप में शराब की बिक्री	समस्त विनिर्माण उद्योग में शराब की बिक्री % के रूप में
दुर्गा	2,665	1.36	0.4
सरगुजा	1,269	25.3	0.55
जगदलपुर	15	69.3	1.69
जांजगीर चांपा	29	19.6	0.5
रायगढ़	3,125	2.6	0.99
मुंगेली	68	2.99	06.9
सुकमा	998	5.97	11.6
बलौदा बाजार	655	5.69	0.16
बलरामपुर	29	4.97	0.10
नारायणपुर	299	5.98	0.25
कोरिया	24	6.79	0.99
धमतरी	1,399	2.69	1.066

"वनतबमेरू ीजजचेरूध्ध्मगबपेमण्बहण्दपबण्पदध्बेउबसध्ठसंबास्पेजमक

राष्ट्रीय स्तर पर, शराब उद्योग ने 2005–2006 के दौरान राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 0.1ः का योगदान दिया। इस योगदान को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, कपड़ा जैसे राजनीतिक प्रभाव वाला एक क्षेत्र, जिसे बड़ा माना जाता है और जिसका आर्थिक योगदान है महत्वपूर्ण माने जाते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में 4ः से 5ः के बीच योगदान करते हैं तालिका 2।

तालिका 2 छत्तीसगढ़ में शराब और चयनित प्रमुख उद्योगों के बीच रोजगार और कारोबार की तुलना।

वर्ग	शराब	कपड़ा
रोजगार	6.39	36
वार्षिक कारोबार	43.6	1699
सकल घरेलू उत्पाद का टर्नओवर हिस्सा	0.26%	5.6%

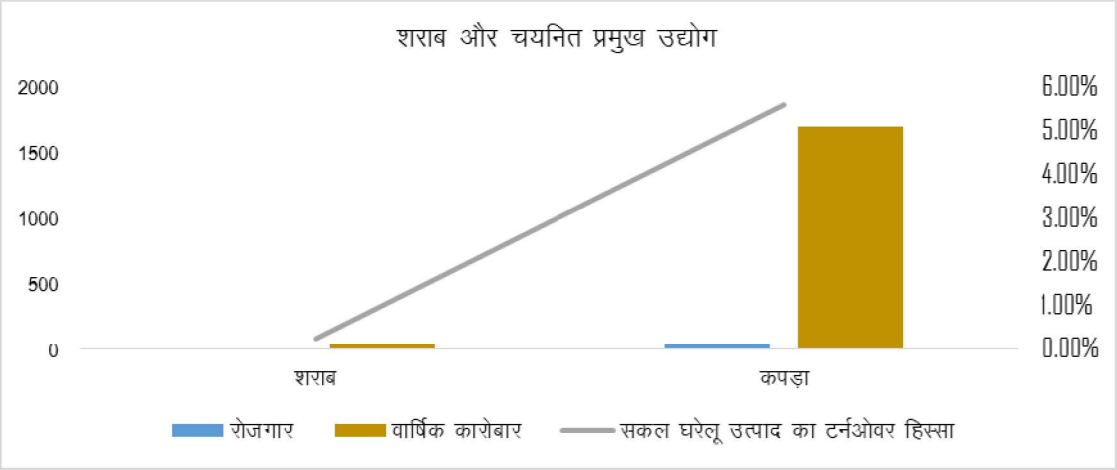

आकृति 1 छत्तीसगढ़ में शराब और चयनित प्रमुख उद्योगों के बीच रोजगार और कारोबार की तुलना

3. रोजगार और मजदूरी–

हमारा अनुमान है कि 2005–2006 में शराब निर्माण में 4.16 मिलियन कर्मचारी कार्यरत थे। इसमें 3.42 मिलियन कर्मचारी पूर्णकालिक काम में लगे हुए थे जबकि 0.74 मिलियन कर्मचारी अंशकालिक काम में लगे हुए थे। असंगठित विनिर्माण रोजगार में शराब क्षेत्र का हिस्सा लगभग 11: है, और छत्तीसगढ़ में कुल रोजगार में पूर्णकालिक श्रमिकों की हिस्सेदारी लगभग 0.74: है, 2004 में लगभग 457 मिलियन औपचारिक श्रमिकों का अनुमान है।38 जिसमें पूर्णकालिक और अंशकालिक श्रमिक शामिल हैं, शराब क्षेत्र कुल रोजगार में 0.9: योगदान दिया।

श्रमिकों की संख्या के लिए उपरोक्त अनुमान (जिसमें मालिक, किराए पर काम करने वाले और सहायक शामिल हैं – जिन्हें आवश्यक रूप से नियमित वेतन नहीं मिलता है) 10 मिलियन शराब श्रमिकों के ट्रेड यूनियन के दावों से काफी कम है। इसकी तुलना में, कपड़ा जैसे बड़े उद्योग लगभग 35 मिलियन श्रमिकों को सीधे रोजगार देते हैं (तालिका 3)। हथकरघा क्षेत्र, जो एक कुटीर उद्योग है और संरचनात्मक रूप से शराब के समान है (दोनों असंगठित घरेलू उद्योग हैं जिनमें महिलाओं और बच्चों से भी श्रम इनपुट होता है), लगभग 6.5 मिलियन लोगों को रोजगार देता है।

शराब उद्योग में वेतन संवेदनशीलता का मतलब है कि श्रमिक, विशेष रूप से गरीब और ग्रामीण महिलाएं, वेतन भेदभाव, उत्पीड़न और शोषण के प्रति संवेदनशील हैं।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, अध्ययनों से पता चला है कि किसी भी शराब निर्माता फर्म द्वारा न्यूनतम वेतन कानूनों का पालन नहीं किया गया था। 30 43 तालिका 3 से पता चलता है कि शराब श्रमिकों को दिया गया कुल मुआवजा असंगठित विनिर्माण में श्रमिकों के मुआवजे का केवल 0.38: और 0.09: था। 2005–2006 में सभी का विनिर्माण।

जबकि शराब उद्योग सभी असंगठित विनिर्माण श्रमिकों में से लगभग 11: को रोजगार देता है, लेकिन उन्हें आनुपातिक तरीके से मुआवजा नहीं दिया जाता है। इसके विपरीत, असंगठित खाद्य विनिर्माण (2.8:) और असंगठित कपड़ा विनिर्माण (4.3:) जैसे उद्योग कुल मुआवजे के हिस्से के रूप में काफी अधिक योगदान देते हैं, भले ही वे कुल रोजगार का केवल 1.4: बनाते हैं।

तालिका 3 छत्तीसगढ़ में शराब उत्पादक जिलों में शराब निर्माताओं को मुआवजे का अनुमानित हिस्सा।

जिला	कुल मुआवजा प्राप्तियां	% असंगठित विनिर्माण उद्योग के रूप में शराब मुआवजा	सभी विनिर्माण उद्योग के % के रूप में शराब मुआवजा
बिलासपुर	1,269	55.3	0.22
रायपुर	2,561	5.69	0.65
दुर्ग	269	4.65	0.69
सरगुजा	1,522	2.36	1.06
जगदलपुर	297	4.69	04.6
जांजगीर चांपा	556	4.33	0.26

जिला	कुल मुआवजा प्राप्तियां	% असंगठित विनिर्माण उद्योग के रूप में शराब मुआवजा	सभी विनिर्माण उद्योग के % के रूप में शराब मुआवजा
रायगढ़	297	1.98	2.6
मुंगेली	22	4.69	0.69
सुकमा	69	5.98	0.44
बलौदा बाजार	48	2.49	0.01
बलरामपुर	66	2.36	0.22
नारायणपुर	1,236	11.9	0.96
कोरिया	1,698	5.98	0.16
धमतरी	26	25.6	0.67

ॅवनतबमेरू ीजजचेरूध्मगबपेमण्बहण्दपबण्पदब्बेउबसध्ठसंबास्पेजमक

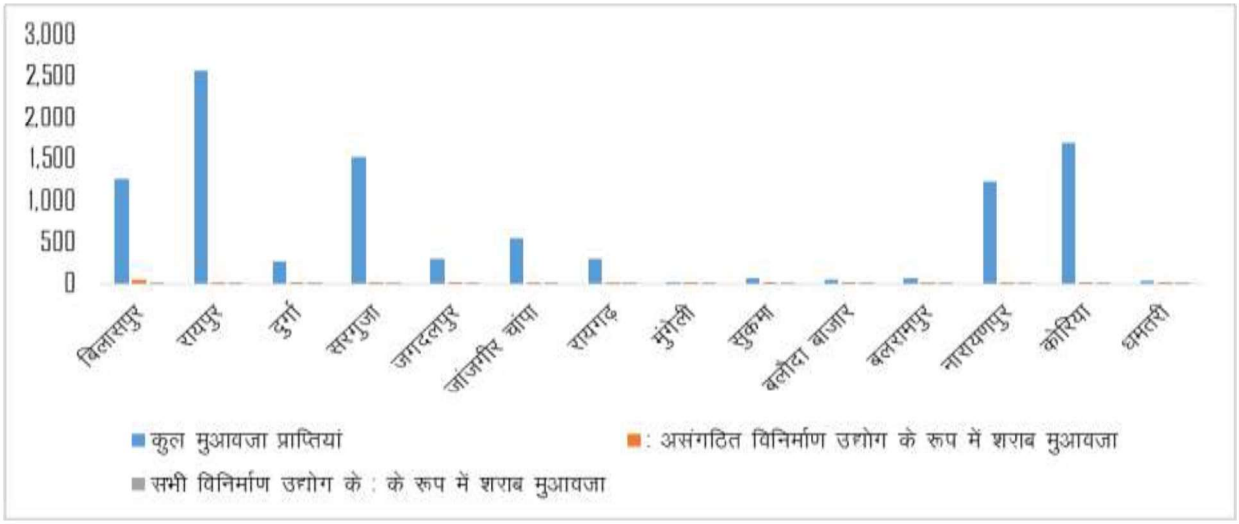

आकृति 2 छत्तीसगढ़ में शराब उत्पादक जिलों में शराब निर्माताओं को मुआवजे का अनुमानित हिस्सा।

जबकि उद्योग के समर्थक अक्सर सरकारी कार्रवाई के खिलाफ तर्क देने के लिए इसके आर्थिक योगदान का उपयोग करते हैं, यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक संक्रमण – जैसा कि मुक्त बाजार ताकतों द्वारा निर्धारित होता है – दीर्घकालिक विकास, राष्ट्रीय आय में वृद्धि और गरीबी में कमी के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में. उदाहरण के लिए, यहां तक कि जो क्षेत्र, आकार और संरचना में शराब उद्योग के समान है, गिरावट का अनुभव कर रहा है और श्रमिक उद्योग से दूर हो रहे हैं। 44–46 वैश्वीकरण और पावरलूम में तकनीकी बदलाव के कारण प्रतिस्पर्धा ने इसमें योगदान दिया है गिरावट, सरकार ने समय के साथ उद्योग को अपनी वित्तीय सहायता कम कर दी। हालाँकि, शोधकर्ताओं ने पाया है कि हथकरघा बुनकरों ने स्पष्ट रूप से बाजार परिवर्तन का सामना किया है।

निष्कर्ष–

इस पेपर में, हम यह पता लगाने के लिए फर्म–स्तरीय डेटा का उपयोग करते हैं कि असंगठित शराब विनिर्माण उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक छोटा योगदानकर्ता है। लगभग 457 मिलियन नियोजित व्यक्तियों वाले देश में, शराब उद्योग में केवल 4.2 मिलियन पूर्णकालिक और अंशकालिक कर्मचारी कार्यरत हैं। क्षेत्रीय स्तर पर, शराब विनिर्माण केवल कुछ जिलों में रोजगार और आर्थिक गतिविधि में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

राष्ट्रीय स्तर पर, शराब उद्योग की वार्षिक बिक्री (31.6 अरब रुपये) कपड़ा उद्योग जैसे आर्थिक महाशक्तियों (1350 अरब रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार) से बहुत कम है। रोजगार के संबंध में, शराब विनिर्माण क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या हथकरघा उद्योग के बराबर है, जो लगभग 6.5 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। हालांकि किसी भी अध्ययन ने छत्तीसगढ़ में उद्योग पर उच्च शराब बिक्री करों के प्रभाव का अनुमान लगाने का प्रयास नहीं किया है, शोधकर्ताओं का तर्क है कि इस तरह के कानून का वृहद स्तर पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।50 51 इनपुट आउटपुट मॉडल का उपयोग करते हुए, अधिकांश स्वतंत्र अध्ययन नगण्य अनुमान लगाते हैं शराब पर खर्च खत्म करने या कम करने से आर्थिक गतिविधियों पर असर।

उच्च शराब करों के सामाजिक आदान–प्रदान का मूल्यांकन करते समय, हमें न केवल नौकरियों बल्कि नौकरियों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य प्रभावों पर भी विचार करना चाहिए। मूल समझौता 1 मिलियन शराब पीने से होने वाली मौतों के बीच है, जिनमें से 70: 30–69 वर्ष की उत्पादक आयु के दौरान होती हैं, और कुछ मिलियन शराब उद्योग की नौकरियां जिन्हें अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है। शराब पर कर बढ़ाने से कर राजस्व में अरबों रुपये बढ़ सकते हैं और लाखों लोगों को शराब पीने से रोका जा सकता है। रूढ़िवादी रूप से, प्रत्येक शराब की नौकरी का आर्थिक उत्पादन लगभग रुपये है। 7600 (यूएस+143) सालाना, जिसके परिणामस्वरूप हमारे डेटा में कुल 713 मिलियन डॉलर का उत्पादन हुआ। इसकी तुलना में, अकेले शराब पीने से संबंधित सभी बीमारियों के इलाज की प्रत्यक्ष चिकित्सा लागत 2004 में 907 मिलियन डॉलर आंकी गई थी, जिसमें से अधिकांश शराब पीने के कारण हुई थी। शराब पीने से होने वाली लगभग 10 लाख मौतों से असामयिक मौतों और गरीबी के जाल से होने वाली आर्थिक क्षति निश्चित रूप से परिमाण का एक बड़ा क्रम है।

संदर्भ

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन (2014) शराब और स्वास्थ्य पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट।
2. देवांगन ए सके, साहू केआर, सोनी एस के। जनजाति के बीच रेशम उत्पादन के माध्यम से गरीबी को दूर करना–छ.ग. के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ ब्लॉक का एक सामाजिक–आर्थिक अध्ययन। (छत्तीसगढ़). हालिया विज्ञान के अनुसंधान जर्नल। 2012य 1रू371–374।
3. बोनू एस, रानी एम, पीटर्स डीएच, झा पी, गुयेन एसएन। 2005. क्या शराब या एल्कोहॉल के सेवन से छत्तीसगढ़ में अस्पताल में भर्ती होने का खर्च गरीबी में बढ़ता है? स्वास्थ्य नीति और योजनाय 20(1)रू 41–49।
4. ब्रह्मचारी बीएन एट अल.. छत्तीसगढ़ में तसर रेशमकीट पालकों, रीलर्स और बुनकरों का सामाजिक–आर्थिक अध्ययन। वार्षिक रिपोर्ट, सीटीआर एवं टीआई, रांची। 2006.
5. चन्द्रशेखर आर. धर्मपुरी जिले के होसुर तालुक में वैकल्पिक फसलों की तुलना में रेशम उत्पादन में आय और रोजगार सृजन। एम.एससी थीसिस, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय. बैंगलोरल 1985।
6. रेशम उत्पादन विभाग. छत्तीसगढ़, विस्तृत रिपोर्ट. सोनाखान भवन, रायपुर 2017.।
7. देवांगन एसके एट अल। रेशम उत्पादन – जनजातीय के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र की जाँच का एक उपकरण। पर्यावरण अनुसंधान और विकास जर्नल. 2011, 6(1).
8. सक्सेना एस. छत्तीसगढ़ में शराब पर देश प्रोफाइल, 8 विकासशील देशों में शराब और सार्वजनिक स्वास्थ्य।
9. आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेडय 2012 अप्रैल 18.
10. मधुसूदन सिंह सोलंकी, (2014)। शराब सेवन विकार. राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल.
11. बेनेट एलए, कैम्पिलो सी, चन्द्रशेखर सीआर, गुरेजे ओ. (1998) छत्तीसगढ़, मैक्सिको और नाइजीरिया में मादक पेय की खपतरू एक अंतर–सांस्कृतिक तुलना। अल्कोहल स्वास्थ्य अनुसंधान विश्व, 22(4), 243–52।
12. गिरीश एन, कविता आर, गुरुराज जी, बेनेगल वी. (2010) शराब का उपयोग और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए निहितार्थरू चार समुदायों में उपयोग के पैटर्न। छत्तीसगढ़ जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, 35रू238–44।